



Government of India

National Commission for Scheduled Castes

(A Constitutional body set up under Article 338 of the Constitution of India)

5th Floor, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003

Dated: 03.07.2024

File No. 27/09/UP/2022/ESDW

To,

The District Magistrate,
District – Kanpur,
Uttar Pradesh 208001
Email: dmkap@nic.in

Sub: New item appeared in Prabhat Khabar Digital Desk, Kanpur, dated 18-09-2022 under captioned “कानपुर में सीवर टैंक में उतरे मजदूरों की मौत, एक ने मौके पर और दो ने अस्पताल में तोड़ा दम” ।

Sir/Madam,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of the meeting held on **12.06.2024** in the chamber of Shri Love Kush Kumar, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Castes for necessary action.

It is therefore, requested that the **action taken report** in the matter may please be furnished to this Commission.

Yours faithfully

(Prabhat Mohan Thakur)
Research Officer

Encl: As above



सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES
(A Constitutional body set up under Article 338 of the Constitution of India)

फाइल संख्या- 27/09/यूपी/2022/ईएसडीडब्ल्यू
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

आयोग में दिनांक 12.06.2024 को हुई सुनवाई का कार्यवृत्त

प्रकरण में दिनांक 12.06.2024 को सुनवाई की गई थी। श्री सूरज कुमार यादव, अपर जिलाधिकारी, (न्यायिक) कानपुर उपस्थित हुए।

दैनिक समाचार पत्र प्रभात खबर डिजिटल डेस्क, कानपुर दिनांक 18.09.2022 में शीर्षक "कानपुर में सीवर टैंक में उतरे मजदूरों की मौत, एक ने मौके पर और दो ने अस्पताल में तोड़ा दम " समाचार प्रकाशित हुआ था। समाचार पत्र के अनुसार घटना स्थल पर सीवर लाइन में सफाई करने के दौरान एक मजदूर की मृत्यु हो गयी (श्री शिवा तिवारी) जिसको बचाने के लिए दो अन्य मजदूर (श्री अंकित पाल व अमित कुमार) सीवर लाइन के अंदर गए जहां पर उन दोनों की भी दम घुटने के कारण मृत्यु हो गयी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने समाचार पत्र में प्रकाशित इस खबर पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबन्धित अधिकारियों को मामले में कृत कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने हेतु नोटिस जारी किए थे। परंतु निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

2. प्रकरण में सुनवाई की गई। अपर जिलाधिकारी, कानपुर ने मामले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की और आयोग को अवगत कराया कि मृतक तीनों सफाईकर्मियों को सीवेज टैंक की सफाई हेतु निजी कंपनी द्वारा पारिश्रमिक पर रखा था। तदुपरान्त टैंक की सफाई व सटरिंग खोलते समय जहरीली गैस से दम घुटने के कारण तीनों सफाईकर्मियों की मृत्यु हो गयी थी। कानपुर जिला प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को राज्य शासन द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में दिनांक 10.06.2024 को आर्थिक सहायता रुपये 04 लाख स्वीकृत कर संबन्धित राशि को उनके बैंक खाते में जमा करा दिया है। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई थी। पीड़ित पक्षों एवं विरोधी पक्ष के बीच आपसी समझौता होने के कारण पीड़ित पक्ष ने मामले में कोई भी एफ़आईआर दर्ज कराने मना कर दिया था।

3. मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद आयोग निमलिखित अनुसंशाये करता है।

- जिला प्रशासन मृतक के माता पिता को पेंशन दिये जाने, विवाहित मृतक की पत्नी को विधवा पेंशन या नौकरी दिए जाने, एवं बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। ।

1
27/6/2024



- तीनों मृतकों के आश्रितों को पक्का आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- MS Act, 2013 के अनुसार मृतकों के आश्रितों को रूपये 10 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाये।
- जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सीवरों की सफाई के संबंध में PEMSR Rules, 2013 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करने तथा MS Act, 2013 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तत्काल संस्थागत कदम उठाए जाये। इसके अलावा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने की हेतु उचित कदम उठाए जाए ।
- MS Act, 2013 एवं PEMSR Rules, 2013 के प्रावधानों में दिये गए निर्देशों/दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए और राज्य सरकार/जिला प्रशासन को भी इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए।
- PEMSR Rules, 2013 के नियम 4&5 के अनुसार, जिला प्रशासन सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु अनुबंधित किए गए व्यक्ति को सुरक्षात्मक गियर और सुरक्षा उपकरणों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे। इसके अलावा PEMSR Rules, 2013 के अनुसार यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुरक्षा उपकरणों के बिना सीवर की सफाई किए जाने की अनुमति प्रदान नहीं की जाये। और नियमों के उलंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कारवाही की जाये।
- मशीनों/रोबोट आदि का उपयोग करके सीवेज लाइनों, सेप्टिक टैंकों आदि की शत-प्रतिशत सफाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- जिलाधिकारी, कानपुर आयोग के अनुसंधार्यों पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट एक माह के भीतर आयोग को प्रस्तुत करे।
- कृत कारवाही रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पत्रावली को आयोग में बंद किए जाने हेतु प्रस्तुत किया जाये।


 (लव कुश कुमार)
 सदस्य